ई संदेश

27 अगस्त, 2026 | अंक - 220

सात दिन, सात पृष्ठ

- यूपी के युवाओं के लिए खुलेंगे वैश्विक रोजगार के द्वार
- भारत-जापान के युवा हैं भविष्य के राजदूत: मुख्यमंत्री
- जापान के साथ नई औद्योगिक उड़ान: उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब
- यूपी-जापान के बीच आर्थिक और औद्योगिक सम्बन्धों को नई ऊंचाई देने पर सहमति
- अमर बलिदानियों की स्मृतियों को जीवन्त रखेगी सरकार: मुख्यमंत्री
- मिड-डे मील रसोइयों को मिली बड़ी सौगात: मानदेय अब 3 हजार, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा
- वीर सेनानियों की स्मृतियां राष्ट्रसेवा की प्रेरणा: मुख्यमंत्री
- विकास और विरासत से रायबरेली को मिली नई पहचान: मुख्यमंत्री
- आत्मनिर्भर युवा उत्तर प्रदेश के विकास का आधार: मुख्यमंत्री
- यू0पी0 एग्रीज से प्रदेश में आएगी स्मार्ट एग्रीकल्चर क्रांति: मुख्यमंत्री
- प्रदेश की सभी वरिष्ठ महिलाओं को मिली आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सौगात
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 25 अगस्त, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

यूपी के युवाओं के लिए खुलेंगे वैश्विक रोजगार के द्वार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 20 अगस्त, 2026 को अपने सरकारी आवास पर व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग की कार्ययोजना की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश के युवाओं को आधुनिक कौशल, उद्योग आधारित प्रशिक्षण और वैश्विक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी कौशल हब बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

युवाओं के सुनहरे भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आई0टी0आई0 संस्थानों को अधिक से अधिक उद्योगों से जोड़ा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उद्योगों की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार ही पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण विकसित किए जाएं, जिससे युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार किया जा सके।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने आगे कहा कि संस्थानों में अप्रेन्टिसशिप तथा ऑन-जॉब प्रशिक्षण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर और त्वरित अवसर सृजित होंगे। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कौशल विकास को अब केवल स्थानीय स्तर तक सीमित न रखकर इसे रोजगार के वैश्विक अवसरों के साथ भी जोड़ा जाना चाहिए।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आई0टी0आई0 और उद्योगों के बीच निरन्तर संवाद की एक सुदृढ़ और स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही, उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर नियमित रूप से रोजगार मेलों का आयोजन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि युवाओं को उनके घर के समीप ही रोजगार के मंच उपलब्ध हो सकें।

सेण्टर फॉर इनोवेशन, इन्वेन्शन, इन्क्यूबेशन एण्ड ट्रेनिंग (सी0आई0आई0आई0टी0) केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली केन्द्रों का संचालन अतिशीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इन केन्द्रों को आधुनिक तकनीक और उद्योग आधारित प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता को सर्वोपरि बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके लिए अनुदेशकों की पर्याप्त उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चयनित अनुदेशकों को नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में उनके अनुभव और कार्य क्षमता के आधार पर वेटेज देने का प्राविधान अवश्य किया जाए।

प्रदेश के गरीब तबके के उत्थान पर बात करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जीरो पॉवर्टी अभियान से जुड़े परिवारों के बच्चों और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि अब कौशल प्रशिक्षण की वास्तविक सफलता का आकलन केवल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या गिनाने से नहीं, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के धरातलीय परिणामों से किया जाएगा।

वैश्विक परिदृश्य का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों में कुशल जनशक्ति की भारी मांग है। इसे देखते हुए उन्होंने युवाओं के लिए विदेशी भाषाओं का डिजिटल प्रशिक्षण जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर हिन्दी की आधिकारिक शब्दावली के प्रयोग के साथ-साथ प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण भी अनिवार्य किया जाए ताकि हमारे युवा विश्व पटल पर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकें।

भारत-जापान के युवा हैं भविष्य के राजदूतः मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 21 अगस्त, 2026 को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश-जापान निवेश बैठक-2026 के क्रम में आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम 'ए डायलॉग विद द फ्यूचर' में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी तथा जापान के यामानाशी प्रान्त के गवर्नर श्री कोटारो नागासाकी की गरिमामयी उपस्थिति में यामानाशी से आए 13 विद्यार्थियों व उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ सार्थक संवाद किया।

मुख्यमंत्री जी ने जापानी अभिवादन 'ओहायो गोजाइमासु' के साथ विदेशी अतिथियों और लखनऊ के युवा साथियों का आत्मीय स्वागत किया। अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केन्द्र है। उन्होंने अवध क्षेत्र को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि बताते हुए इसे भारत का हृदय स्थल करार दिया।

पर्यटन और संस्कृति का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जापानी विद्यार्थियों ने आगरा का ताजमहल देखा है और अब उन्हें वाराणसी तथा सारनाथ जाने का अवसर मिलेगा, जो भारत की आध्यात्मिकता, संस्कृति और सभ्यतागत विरासत को करीब से जानने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अवसर केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों और दो देशों की युवा पीढ़ियों का ऐतिहासिक संगम है।

आगामी वर्ष दोनों देशों के राजनयिक सम्बन्धों के 75 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ये विद्यार्थी भविष्य के राजदूत के रूप में इस सम्बन्ध को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह संवाद जापानी विद्यार्थियों के लिए भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना और विविधता को समझने का मंच है, वहीं भारतीय विद्यार्थी इसके माध्यम से जापान के अनुशासन, 'इकीगाई', समयबद्धता और टीमवर्क जैसी श्रेष्ठ बातों को सीख सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और जापान के सामाजिक सामंजस्य के बीच की सुन्दर समानता को रेखांकित किया। इसी क्रम में उन्होंने आगे कहा कि जापान के नवाचार, आत्मअनुशासन व गुणवत्ता और भारत की युवा शक्ति व सृजनात्मकता के एक साथ आने से वैश्विक स्तर पर नई सम्भावनाओं के द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने विद्यार्थियों से एक-दूसरे की संस्कृति का सम्मान करने का आह्वान करते हुए अपना सम्बोधन जापानी भाषा में 'अरिगातो गोजाइमासु' कहकर समाप्त किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यामानाशी प्रान्त के गवर्नर श्री कोटारो नागासाकी ने इस विशेष अवसर के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। गवर्नर ने कहा कि दोनों देशों को बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए आपसी समानताओं और भिन्नताओं को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने यामानाशी की सोच और भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को एक समान बताते हुए युवाओं से आह्वान किया कि यह मुलाकात एक दिन का कार्यक्रम न रहे, बल्कि इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए दोनों देश साथ मिलकर समृद्ध हों।

संवाद के दौरान जापानी विद्यार्थियों की रचनात्मक गतिविधियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। जापानी विद्यार्थियों ने मिलकर अपनी भाषा में एक मधुर गीत प्रस्तुत किया, जबकि भारत की ओर से ईशान ने 'कौशल्या दशरथ के नंदन' गाकर यह साबित कर दिया कि भावनाएं दिलों को जोड़ती हैं। लखनऊ की छात्रा अक्षरा पाण्डेय ने 'अतिथि देवो भव' की भावना के साथ अतिथियों का स्वागत किया और डोरेमोन देखते हुए बड़े होने की अपनी बचपन की सुखद यादें साझा कीं।

इस अवसर पर जापानी छात्र कज़ामा ने भारत में मिले मित्रवत व्यवहार को दिल छू लेने वाला बताया और भारी यातायात को अपने लिए टोक्यो से बिल्कुल अलग व नया अनुभव करार दिया। वहीं, छात्रा मियागी मोतो ने अलग-अलग संस्कृतियों को समझने पर जोर देते हुए शांति और मैत्री की प्रार्थना की। जापानी विद्यार्थियों ने कागज़ से बनी सुन्दर ओरिगेमी कला के जरिए मुख्यमंत्री जी को शांति व मित्रता का सन्देश भेंट किया। अंततः मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्यार्थियों के साथ ली गई सेल्फी ने इस कार्यक्रम को निवेश से परे मानवीय रिश्तों का एक भव्य उत्सव बना दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 20 अगस्त, 2026 को उनके सरकारी आवास पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली ने भेंट की।

जापान के साथ नई औद्योगिक उड़ानः उत्तर प्रदेश बनेगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 21 अगस्त, 2026 को लखनऊ में आयोजित 'उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेण्ट मीट-2026' में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने जापान में रोजगार प्राप्त करने वाले दो होनहार छात्रों को सम्मानित किया और जापानी प्रतिनिधिमण्डल के साथ आयोजन स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में तीन महत्वपूर्ण एमओयू का आदान-प्रदान किया गया तथा जापान और उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील साझेदारी पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश अपने एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट्स और आधुनिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से निवेश और रोजगार के नए अवसरों का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल कनेक्टिविटी बेहतर करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इको-सिस्टम तैयार करना है जो इंडस्ट्री को स्पीड, आम नागरिक को सेफ्टी और निवेशकों को रिलायबिलिटी दे सके। मुख्यमंत्री जी ने जापान के अनुशासन, 'काइज़ेन', 'मोनोज़ुकुरी' और 'शिंकानसेन' (बुलेट ट्रेन) कार्यसंस्कृति की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का तीव्र विकास किया जा रहा है।

जापानी निवेश को सुगम बनाने की दिशा में निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत एक डेडिकेटेड 'यामानाशी डेस्क' स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह डेस्क यामानाशी सरकार और निवेशकों के बीच निरंतर समन्वय स्थापित करेगा तथा हर 90 दिन में निवेश परियोजनाओं की गहन समीक्षा की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर कोई गैप न रहे। मुख्यमंत्री जी ने यामानाशी के गवर्नर द्वारा यूपी में एमएसएमई कंपनियों के निवेश के लिए घोषित 600 करोड़ रुपये के फंड पर उनका विशेष आभार व्यक्त किया और इसे जापानी उद्योग जगत के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया।

युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी और जापानी डेलीगेशन के बीच एमओयू सम्पन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों व संस्थानों को भी जापानी संस्थानों से जोड़ा जाएगा, ताकि हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, पॉलिटेक्निक और नर्सिंग के छात्रों को जापानी भाषा तथा ग्लोबल वर्क कल्चर में प्रशिक्षित कर बेहतरीन रोजगार उपलब्ध कराए जा सकें।

पर्यटन और आधुनिक तकनीक के विषय में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के साथ 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस उन्नत तकनीक पर यामानाशी के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम होगा और अक्टूबर 2026 में यामानाशी में होने वाली इंटरनेशनल हाइड्रोजन समिट में उत्तर प्रदेश अपना एक विशेष प्रतिनिधिमंडल भी भेजेगा।

सांस्कृतिक समानताओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत और जापान के बीच भगवान बुद्ध से जुड़ी साझी विरासत और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का गहरा संबंध है। वर्ष 2047 के विजन को साझा करते हुए उन्होंने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में सह-निर्माता (को-क्रिएटर) बनने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि आज 2047 के उद्योगों की रूपरेखा तैयार हो रही है और सरकार चाहती है कि जापान तथा यूपी मिलकर इसे डिजाइन करें। इस ऐतिहासिक मीट में यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर श्री कोटारो नागासाकी, राज्य के पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' सहित कई गणमान्य जन उपस्थित रहे।

यूपी-जापान के बीच आर्थिक और औद्योगिक सम्बन्धों को नई ऊंचाई देने पर सहमति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दिनांक 21 अगस्त, 2026 को उनके सरकारी आवास पर भारत में जापान के राजदूत श्री केइची ओनो ने एक शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर प्रदेश और जापान के मध्य निवेश, उन्नत प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, मानव संसाधन विकास, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को और व्यापक बनाने पर विस्तार से सार्थक चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री जी ने जापानी राजदूत से कहा कि उत्तर प्रदेश जापान के साथ अपने आर्थिक और औद्योगिक सम्बन्धों को नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जापान के निवेशकों के लिए एमएसएमई (MSME) से लेकर बड़े उद्योगों तक व्यापक अवसर उपलब्ध हैं और दोनों पक्षों के पारस्परिक सहयोग से इन अपार सम्भावनाओं को ठोस परिणामों में बदला जा सकता है।

भेंट के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग पर विशेष रूप से विचार-विमर्श हुआ। जापानी राजदूत ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि जुलाई 2026 में जापान के प्रधानमंत्री श्री ताकाइची की भारत यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर को जापान-भारत आर्थिक सुरक्षा सहयोग के पाँच प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। इसी क्रम में जापानी उद्योग जगत की एक टीम सितम्बर के मध्य में 'सेमीकॉन इण्डिया' के साथ एचसीएल (HCL) टेक्नोलॉजीज का दौरा करेगी।

जापानी पक्ष ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए अपनी टीम के जल्द ही उत्तर प्रदेश दौरे की भी बात कही। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता के बीच सहयोग की असीम सम्भावनाएँ हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की सेमीकंडक्टर समिति की बैठक में सहभागिता पर भी चर्चा हुई।

जापानी कम्पनियों के लिए निवेश की सम्भावनाओं पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश का विशाल बाजार, बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत औद्योगिक आधार और तेजी से विकसित हो रहा आधारभूत ढांचा जापानी कम्पनियों को एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा स्थित 'जापान सिटी' इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। जेईटीआरओ (JETRO) और जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के सहयोग से प्रदेश में जापानी निवेश को और विस्तार देने पर भी रूपरेखा तय की गई।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यामाहा, डेंसो, एनटीटी (NTT) डेटा, टोयो इंक और पैनासोनिक जैसी प्रतिष्ठित जापानी कम्पनियाँ उत्तर प्रदेश में पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। इसके अलावा, जापान सिटी के निकट कुबोटा द्वारा ट्रैक्टर और निर्माण मशीनरी के विनिर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास बड़ी संख्या में युवा शक्ति है, जिनका जापानी उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल विकास किया जा सकता है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएं, जहाँ युवाओं को जापानी उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण मिल सके।

रोजगार के अवसरों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि जापान के तकनीकी प्रशिक्षण और विशिष्ट कौशल श्रमिक कार्यक्रमों से प्रदेश के युवाओं को जापान में काम करने का अवसर मिल रहा है। विनिर्माण, कृषि और नर्सिंग केयर क्षेत्रों में रोजगार पर मंथन हुआ, जिसमें मार्च में आगरा के आरबीपीजी कॉलेज में आयोजित कृषि रोजगार मेले और एमिटी विश्वविद्यालय तथा जापान के इबाराकी प्रीफेक्चर के बीच विद्यार्थियों की इंटर्नशिप के समझौते को अहम पहल बताया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जापानी भाषा और तकनीकी दक्षता को साथ लेकर युवाओं के लिए जापान में अवसर और व्यापक बनाए जा सकते हैं।

पर्यटन सहयोग पर चर्चा के दौरान जापानी पक्ष ने सितम्बर में आयोजित होने वाले 'टूरिज्म एक्सपो जापान-2026' में उत्तर प्रदेश की सहभागिता का अनुरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की ओर से अपनी सहमति प्रदान की। दोनों पक्षों ने माना कि यह आयोजन यूपी के बौद्ध, आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन स्थलों को जापानी पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत करने का बड़ा अवसर है। यह भी बताया गया कि वर्ष 2025 में 2.19 लाख जापानी नागरिकों ने भारत की यात्रा की, जो पिछले वर्ष से 12.5 प्रतिशत अधिक है।

बैठक में सारनाथ और जापान के नारा के मध्य बौद्ध एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को दोनों देशों के ऐतिहासिक जुड़ाव का प्रतीक बताया गया। वर्ष 2027 में भारत और जापान के राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर को पर्यटन, संस्कृति व जनस्तरीय सम्बन्धों को और प्रगाढ़ करने के रूप में देखा गया।

वर्तमान में चल रही उत्तर प्रदेश-जापान निवेश बैठक का उल्लेख करते हुए बताया गया कि जापान के उद्योग जगत के 200 से अधिक प्रतिनिधियों का दल इस समय उत्तर प्रदेश की यात्रा पर है। जापानी निवेशकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुए इस संवाद के परिणामस्वरूप अनेक एमओयू (MoU) हस्ताक्षरित हुए हैं, जिनसे प्रदेश में लगभग 10 हजार रोजगार के नए अवसर सृजित होने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 21 अगस्त, 2026 को उनके सरकारी आवास पर यामानाशी प्रीफेक्चर, जापान के गवर्नर श्री कोटारो नागासाकी ने शिष्टाचार भेंट की।

अमर बलिदानियों की स्मृतियों को जीवन्त रखेगी सरकार: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 23 अगस्त, 2026 को भारत माता के महान सपूत अमर शहीद स्व0 श्री गुलाब सिंह लोधी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। स्वाधीनता संग्राम सेनानी के बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम से पूर्व, उन्होंने स्वामी विवेकानन्द जी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर नमन किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज हम सभी अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की पुण्य स्मृतियों को नमन कर रहे हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर भारत की आन-बान-शान को बनाए रखा। उन्होंने बताया कि शहीद गुलाब सिंह लोधी का जन्म वर्ष 1903 में उन्नाव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। आजादी के आन्दोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने वाले इस अमर बलिदानी ने लखनऊ आकर देश की स्वाधीनता के लिए स्वयं का उत्सर्ग कर दिया।

मुख्यमंत्री जी ने स्मरण कराया कि 23 अगस्त, 1935 को मात्र 32 वर्ष की आयु में ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती देते हुए अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी ने स्वाधीनता के प्रतीक तिरंगे को इसी पार्क में लहराने का साहसिक कार्य किया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कायर ब्रिटिश हुकूमत ने उनके इस अदम्य पराक्रम पर उन्हें गोलियों से भून दिया था। अपने प्राणों की आहुति देकर वे भारत की स्वाधीनता का एक स्वर्ण पृष्ठ आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप मात्र 12 वर्ष पश्चात देश ब्रिटिश दासता से मुक्त हो गया।

अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार अपने सभी अमर बलिदानियों के पुण्य स्मरण को जीवन्त बनाए रखने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि शहीद गुलाब सिंह लोधी की स्मृतियों को संजोने के लिए राज्य सरकार ने जनपद उन्नाव में पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र और पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र का नामकरण उनके नाम पर करते हुए उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इसी भावना के तहत 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर में स्वयं को बलिदान करने वाली वीरांगना अवन्तीबाई लोधी के नाम पर अलीगढ़ में स्टेडियम और बदायूँ में पीएसी की नई महिला बटालियन का नामकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, लखनऊ में वीरांगना ऊदा देवी पासी तथा गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर पीएसी की महिला बटालियन और औरैया में नए मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर किया गया है।

महान क्रान्तिकारियों और वीर सपूतों के स्मारक बनाने के कार्यक्रम को निरन्तरता प्रदान करने का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में सामाजिक न्याय के योद्धाओं के सम्मान में लगभग 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने बताया कि इस धनराशि से बाबा साहब डॉ0 भीमराव आम्बेडकर, सद्गुरु रविदास जी महाराज और महर्षि वाल्मीकि सहित अन्य महापुरुषों की मूर्तियों पर छाजन लगाने, पार्कों का नवनिर्माण करने और उन्हें सुरक्षित करने का कार्य किया जाएगा। अंत में मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का यह क्रम भविष्य में भी अनवरत आगे बढ़ता रहेगा।

मिड-डे मील रसोइयों को मिली बड़ी सौगात: मानदेय अब 3 हजार, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 23 अगस्त, 2026 को पीएम पोषण योजना के अन्तर्गत कार्यरत मिड-डे मील रसोइयों के सम्मान समारोह में प्रतिभाग करते हुए उनके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रसोइयां केवल भोजन तैयार करने का कार्य नहीं करतीं, बल्कि वे देश के बचपन को स्वस्थ व समर्थ बनाने के अभियान की महत्वपूर्ण सहभागी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने रसोइयों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक, परिधान किट एवं कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि रसोइयों का मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने रसोइयों को 02 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, परिवार सहित प्रतिवर्ष 05 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा और ड्रेस के लिए मिलने वाली धनराशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में 02 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा से सम्बन्धित एमओयू का आदान-प्रदान अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा और भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक के मध्य किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रसोइये विद्यालयों में रसोईघर की स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता और समय से बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि पीएम पोषण योजना के तहत निर्धारित मेन्यू में स्थानीय मिलेट और मौसमी फलों को प्राथमिकता दी जाए और भोजन की गुणवत्ता व बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। मुख्यमंत्री जी ने रसोई में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने और सुरक्षित भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी कड़े निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का घोर अभाव था, लेकिन आज 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, पेयजल और अलग-अलग शौचालयों जैसी सुविधाएं विकसित कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब डीबीटी के माध्यम से यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग की धनराशि सीधे खातों में भेजी जा रही है, जिससे कोई भी गरीब बच्चा भीषण गर्मी या सर्दी में विद्यालय जाने को मजबूर नहीं होता।

मुख्यमंत्री जी ने रसोइयों के योगदान को सराहते हुए कहा कि कोरोना काल और महाकुंभ जैसी चुनौतियों में भी उनका कार्य अनुकरणीय रहा है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा वर्करों और ग्राम चौकीदारों सहित सभी वर्गों को न केवल उचित मानदेय दे रही है, बल्कि उनके लिए सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी भी सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार के इन सुधारों का उद्देश्य केवल विद्यालयों की तस्वीर बदलना नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना है। कार्यक्रम के दौरान पीएम पोषण योजना पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

वीर सेनानियों की स्मृतियां राष्ट्रसेवा की प्रेरणा: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 24 अगस्त, 2026 को जनपद रायबरेली में अवध केसरी एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक राना बेनी माधव बख्श सिंह की 222वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित भाव-समर्पण समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने राना बेनी माधव बख्श सिंह तथा सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ संघर्ष करने वाले सभी वीर सेनानियों और सहयोगियों को नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 21 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित राना बेनी माधव बख्श सिंह स्मृति सभागार का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया तथा 'अवध केसरी' स्मारिका व राना बेनी माधव बख्श सिंह की स्मृति में डाक विभाग के विशेष आवरण का विमोचन भी किया। इससे पूर्व उन्होंने संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और राना बेनी माधव जी के प्रतिमा स्थल के सौन्दर्यीकरण कार्य का लोकार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत आज जिस स्वतंत्रता का अनुभव कर रहा है, उसके लिए अनगिनत लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। उन्होंने बताया कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उत्तर प्रदेश के योगदान के बिना अधूरा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार मंगल पाण्डेय, धन सिंह गुर्जर, नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने देश के विभिन्न हिस्सों से स्वाधीनता संग्राम को नई दिशा दी, उसी प्रकार रायबरेली और अवध क्षेत्र में इस महासंग्राम का कुशल नेतृत्व राना बेनी माधव बख्श सिंह ने किया था।

नवनिर्मित सभागार के उपयोग के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इसका बेहतर ढंग से संचालन एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस सभागार में वर्ष भर साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिवारों को इन आयोजनों में विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित करने की परम्परा विकसित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक और आंतरिक सुरक्षा में लगे पुलिस बल के जवानों के कारण ही हम सुरक्षित हैं, इसलिए ऐसे वीरों और उनके परिजनों के प्रति सम्मान की भावना निरन्तर मजबूत की जानी चाहिए।

समाज को सचेत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत कर देता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। स्वाधीनता संग्राम के महानायकों की स्मृतियों को सुरक्षित रखना और भावी पीढ़ी को उनके त्याग से परिचित कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह नवनिर्मित सभागार केवल एक भवन मात्र नहीं है, बल्कि यह रायबरेली की वीर परम्परा, स्वाभिमान और इसके गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है।

परिसर के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राना बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक परिसर के प्रथम चरण का कार्य 25 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि द्वितीय चरण का कार्य भी निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से निर्देश दिए कि स्वाधीनता संग्राम में सहयोग करने वाले वीरा पासी तथा अन्य प्रमुख सेनानियों के योगदान को भी समान सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए द्वितीय चरण के कार्यों के अंतर्गत परिसर में राना बेनी माधव बख्श सिंह के साथ वीरा पासी एवं अन्य सहयोगियों की प्रतिमाएं स्थापित करने की दिशा में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।

इतिहास को जीवंत बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए हेरिटेज सर्किट और हेरिटेज वॉक जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विरासत के सम्मान के साथ विकास यात्रा को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रायबरेली को केवल रहने और काम करने का स्थान नहीं, बल्कि इसे देखने, समझने और अनुभव करने वाले उत्कृष्ट पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ होने के परिणामस्वरूप ही आज निवेश, उद्योग, पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास धरातल पर उतरा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 24 अगस्त, 2026 को उनके सरकारी आवास पर भारत में थाईलैण्ड की राजदूत सुश्री चवनार्ट थांगसुम्फांत ने शिष्टाचार भेंट की।

विकास और विरासत से रायबरेली को मिली नई पहचान: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 24 अगस्त, 2026 को जनपद रायबरेली में 879 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 346 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। रायबरेली सदर, बछरावाँ और हरचन्दपुर विधान सभा क्षेत्रों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड तथा लैपटॉप प्रदान किए। इसके साथ ही सपेरा समुदाय के आवास विहीन परिवारों को आवासीय पट्टों के आवंटन पत्र भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आज रायबरेली की पहचान बदल चुकी है और इसका नाम पूरे देश में गौरव के साथ लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास आज की आवश्यकता है, जो नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ ही किसानों, कारीगरों और बुजुर्गों का मजबूत संबल बन रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब जिले की एक नई पहचान बन गई है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2012 में बनी यह फैक्ट्री 2014 तक बहुत धीमी गति से चल रही थी, लेकिन वर्ष 2025-26 में यहां 2,156 कोच का रिकॉर्ड निर्माण हुआ है। इसी वर्ष मई में प्रधानमंत्री जी के विजन की वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण कर यहां से रोलआउट भी किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले रायबरेली को केवल वीआईपी जनपद कहा जाता था, लेकिन वहां सुविधाओं का घोर अभाव और बदहाली थी। आज सरकार गरीबों को बिना किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और रोजगार का शत-प्रतिशत लाभ दे रही है।

मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि प्रदेश में घुमन्तु जातियों के लिए घुमन्तु विकास बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके सुखद परिणाम सामने हैं। इसी के तहत सपेरा समुदाय को जमीन के पट्टे और आवास स्वीकृत कर दोहरा लाभ प्रदान किया गया है, ताकि समाज का हर वंचित वर्ग मुख्यधारा से जुड़ सके।

महान सपूत राना बेनी माधव बख्श सिंह जी की 222वीं जयन्ती पर उन्हें नमन करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी स्मृति में एक भव्य ऑडिटोरियम और स्मारक बनाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने वीरा पासी की प्रतिमा स्थापित करने और उनका भव्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की, ताकि स्वाधीनता संग्राम के सभी वीर सेनानियों को पूर्ण व समान सम्मान मिल सके।

विरासत और विकास के समन्वय पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर निर्मित हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की परम्परा और विरासत के बारे में गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए और देश के महापुरुषों, प्रतीकों व धर्मग्रंथों पर चर्चा सकारात्मक भाव से होनी चाहिए।

प्रदेश की सुदृढ़ कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश दंगा, कर्फ्यू और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण बेटियां और व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 16 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन और 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर निर्बाध रूप से मिल रहा है।

कर्मचारियों के हित में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 5 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा और दुर्भाग्यवश दुर्घटना होने की स्थिति में परिवार को 30 से 35 लाख रुपये की सहायता की गारण्टी दी गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश भर के 3,54,000 रसोइयों का मानदेय भी बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 5 लाख रुपये की प्रतिवर्ष चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और ड्रेस के लिए 1,000 रुपये की धनराशि प्रदान कर चार योजनाओं से आच्छादित किया गया है।

अंत में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकास और विरासत के साझा प्रयासों से ही प्रदेश में सुशासन का विश्वास कायम हुआ है। उन्होंने रक्षाबंधन पर्व का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि आगामी 26 अगस्त को प्रदेश की माताओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की जाएगी, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा।

आत्मनिर्भर युवा उत्तर प्रदेश के विकास का आधार: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 25 अगस्त, 2026 को कृषि विभाग में नवचयनित प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) तथा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के मण्डी सचिवों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर युवा ही उत्तर प्रदेश के विकास का वास्तविक आधार हैं। युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और क्षमता से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना करने के लक्ष्य को अभूतपूर्व गति मिल रही है, जिसे आज पूरी दुनिया भी पहचान रही है।

कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के 3,191 प्राविधिक सहायकों तथा 126 मण्डी सचिवों (श्रेणी-3 वर्ग-2) को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री जी ने नवनियुक्त मण्डी सचिवों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वे मण्डियों को स्वच्छ, सुन्दर और व्यवस्थित बनाने में अपना शत-प्रतिशत योगदान दें। उन्होंने बताया कि मण्डियों में कचरे का समुचित निस्तारण, व्यापारियों व किसानों के लिए बुनियादी सुविधाएं, बेहतर शेड और ग्रामीण सड़कों की समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, किसानों की उपज खरीद, एमएसपी की प्रभावी व्यवस्था और मण्डियों को ई-नाम से जोड़ने की कार्यवाही को तेज करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए।

नवचयनित कृषि सहायकों की जिम्मेदारियां तय करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका मुख्य दायित्व किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। उन्होंने ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, आधुनिक कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अब 'लैब टू लैण्ड' की अवधारणा को धरातल पर उतारना होगा। खेती की बात वातानुकूलित कार्यालयों और सेमिनार हॉल के बजाय किसान के खेत में जाकर करनी होगी। उन्होंने कृषि सहायकों को निर्देशित किया कि वे अन्नदाता के प्रति पूर्ण सम्मान व संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

मिशन रोजगार की सफलता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विगत नौ वर्षों में प्रदेश में 9 लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी भेदभाव व पूर्ण पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व की भर्ती प्रक्रियाएं भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद की भेंट चढ़ जाती थीं, लेकिन वर्तमान सरकार ने नकल और भर्ती माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त किया कि आगामी छह माह के भीतर एक लाख और युवाओं को विभिन्न चरणों में सरकारी नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी।

भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी व समयबद्ध बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी आयोगों और बोर्डों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधियाचन प्राप्त होने के एक माह के भीतर विज्ञापन, अगले दो माह में परीक्षा और उसके एक माह में परिणाम जारी करते हुए अधिकतम छह माह के भीतर नियुक्ति पत्र युवाओं के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को भी निर्देशित किया कि वे स्वयं को केवल शिक्षा के केंद्र तक सीमित न रखकर स्किलिंग, कैरियर काउन्सिलिंग और रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करें। मुख्यमंत्री जी ने जापान और इजराइल जैसे देशों द्वारा उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की इच्छा का भी विशेष रूप से उल्लेख किया।

प्रदेश के कृषि विकास और किसानों के हित में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सरकार ने निजी नलकूपों के बिजली बिल के भार को समाप्त कर दिया है और अब किसानों को 10 घण्टे निर्बाध बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को 3 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर लगभग 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है और अब इसे 30 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ में चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक 'सीड पार्क' का निर्माण भी शुरू किया जा रहा है।

सिंचाई परियोजनाओं की सफलता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बाणसागर, अर्जुन सहायक और दशकों से लम्बित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा कर लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है। कार्यक्रम के अंत में कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में 32 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है और प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21 प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

यू0पी0 एग्रीज से प्रदेश में आएगी स्मार्ट एग्रीकल्चर क्रांति: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 26 अगस्त, 2026 को अपने सरकारी आवास पर यू0पी0 एग्रीज योजना के अन्तर्गत आयोजित एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर एवं आदान-प्रदान कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश में कृषि को 'प्रोडक्टिविटी टू प्रॉस्पैरिटी' तथा 'एग्रीकल्चर टू फ्यूचर इकोनॉमी' की ओर ले जाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने इस अवसर पर सभी सहभागी संस्थाओं एवं उनके प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कृषि को नई ऊंचाई देने का संकल्प दोहराया।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार (यूपीडास्प) और गूगल एवं नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी, आई0टी0सी0 तथा एक्वाब्रिज के मध्य चार महत्वपूर्ण एम0ओ0यू0 किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल औपचारिक समझौते नहीं हैं, बल्कि अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि करने, जलवायु अनुकूल कृषि, वैल्यू एडिशन और ग्रामीण उद्यमिता को नई दिशा देने के सामूहिक प्रयास हैं।

मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जी के विजन और विश्व बैंक के सहयोग से लगभग 4,000 करोड़ रुपये की इस यू0पी0 एग्रीज परियोजना को जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है। इसका मुख्य फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 और बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों पर है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 28 जनपदों के 123 विकास खण्डों में कार्य करते हुए 06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जिससे 10 लाख किसानों, 35,000 मत्स्य उत्पादक किसानों और 03 लाख महिला लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुँचेगा।

कृषि पद्धतियों में आ रहे बदलाव का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आई0आर0आर0आई0 के सहयोग से वैज्ञानिक एवं जलवायु अनुकूल कृषि को खेतों तक पहुँचाया जा रहा है, जिसके तहत खरीफ-2026 में 3,000 हेक्टेयर में डायरेक्ट सीडेड राइस (डी0एस0आर0) का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आई0टी0सी0 के साथ मिलकर 02 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही, जनपद बहराइच में 1,500 एकड़ में निर्यात मानकों के अनुरूप धान एक्सपोर्ट क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे किसानों की प्रति एकड़ आय में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

तकनीकी एकीकरण पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गूगल एवं नेटवर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र के लिए एक ओपन डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। यह यूपीआई की तर्ज पर किसानों को मौसम, बाजार, मृदा स्वास्थ्य और कृषि सलाह की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर सुलभ कराएगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एक्वाब्रिज के साथ साझेदारी से उत्तर प्रदेश में एक्वाकल्चर को विज्ञान और उद्यमिता से जोड़कर एक व्यापक 'ब्लू इकोनॉमी' इको-सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसके तहत जनपद उन्नाव में 60 एकड़ में एकीकृत एक्वाकल्चर परियोजना आकार ले रही है।

वैश्विक बाजार से किसानों को जोड़ने की रणनीति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के निकट मेगा फूड पार्क एवं एग्री एक्सपोर्ट सेण्टर विकसित करने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने 'प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजेलिएंस, मार्केट, इण्टरप्राइज = फार्मर प्रॉस्पैरिटी' का नया सूत्र देते हुए कहा कि 21वीं सदी की कृषि केवल मिट्टी और मौसम से नहीं, बल्कि डेटा साइंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट इंटेलिजेंस से संचालित होगी।

अंत में मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य अन्नदाताओं को साथ लेकर ही पूरा किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने सभी को रक्षाबन्धन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और अपनी गतिविधियों के क्रम में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों को ओ0डी0ओ0पी0 (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) उत्पाद भी भेंट किए।

प्रदेश की सभी वरिष्ठ महिलाओं को मिली आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सौगात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 26 अगस्त, 2026 को 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना' का शुभारम्भ करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार आधी आबादी को शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए व्यापक कार्ययोजना के साथ कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को योजना के सांकेतिक कार्ड प्रदान किए तथा उन्हें साड़ी एवं मिष्ठान से युक्त बैग भेंट कर सम्मानित किया। इसके पश्चात उन्होंने विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उपस्थित महिलाओं से संवाद भी किया, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के लिए उनके प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त किया।

योजना के सम्बंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि रक्षाबन्धन पर्व पर 27, 28 और 29 अगस्त को प्रदेश की माताओं, बहनों व बेटियों को परिवहन निगम तथा सिटी बसों में एक सहयात्री के साथ निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त के उपरांत 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना' के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की प्रदेश की सभी महिलाओं को आजीवन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी, जिसके लिए उन्हें केवल अपना वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड दिखाना होगा। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यह सुविधा केवल यात्रा को आसान बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा से सम्मान और स्वावलम्बन से नेतृत्व तक की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस योजना और प्रदेश में बनाए जा रहे कामकाजी महिला छात्रावासों का नामकरण महान शासिका लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर किया गया है, जो महिला स्वावलम्बन, सुशासन और भारत की आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण की अद्भुत प्रतीक थीं। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व महिलाओं की सुरक्षा एक गम्भीर चुनौती थी और योजनाओं में बिचौलियों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश को दंगा एवं कर्फ्यू मुक्त वातावरण मिला है, जिससे उत्सवों में उपद्रव की जगह उल्लास ने ले ली है।

प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज एआई आधारित सेफ सिटी नेटवर्क, '1090', '112' और महिला बीट पुलिस अधिकारियों की तैनाती से सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या मात्र 10 हजार थी, जो अब बढ़कर 45 हजार हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल यह नहीं है कि बेटी घर पहुंचकर सुरक्षित रहे, बल्कि वह घर से बाहर निकले, कार्य करे और रात में भी पूरे अधिकार के साथ सुरक्षित अपने घर लौट सके। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से नाइट शिफ्ट में महिलाओं के कार्य करने के लिए विशेष नीतिगत बदलाव किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज आर्थिक रूप से स्वावलम्बी महिलाओं का आंकड़ा 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जिसे 50 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से 1.10 करोड़ से अधिक परिवारों को निरंतर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक महिलाओं को घरौनी के माध्यम से मालिकाना हक मिला है और आगामी अक्टूबर-नवंबर में प्रदेश की 50 हजार स्नातक बेटियों को स्कूटी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखपति दीदी, बीसी सखी और नमो ड्रोन दीदी जैसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से महिलाएं सीधे टेक्नोलॉजी और वित्तीय सेवाओं से जुड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 31 जनपदों में विभिन्न मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनियों के माध्यम से 4 लाख से अधिक बहनें आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हैं। अंत में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग प्रदेश में हो और वे वैश्विक बाजार तक पहुंचें। इसके साथ ही उन्होंने माताओं-बहनों से अपील की कि वे देश व समाज की सुरक्षा में लगे सैनिकों और पुलिस जवानों को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनके प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापित करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 25 अगस्त, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने गंगा एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने बीडा क्षेत्र, डिफेन्स कॉरिडोर तथा जनपद झांसी के समीप महत्वपूर्ण स्थलों तक प्रदेश एवं देश के अन्य क्षेत्रों से सुरक्षित एवं दुरतगति से यातायात आवगमन हेतु झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का विकास किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
  यह लिंक एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के चैनेज 170$300 (ग्राम फूलपुरा जनपद जालौन के निकट) वाया डिफेन्स कॉरिडोर नोड, गरौठा के निकट से प्रारम्भ होकर उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44) पर अम्बाबाई, जनपद झांसी पर समाप्त होगा।

- लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 में 'सशक्त नारी' शीर्षक के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा व्यवस्था किये जाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। उक्त संकल्प की पूर्ति के क्रम में लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना के माध्यम से प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु की दैनिक रूप से लगभग 88,438 महिला यात्रियों द्वारा मुफ्त यात्रा किये जाने का अनुमान है, जिस पर मासिक 22,55,16,900 रुपये (बाइस करोड़ पचपन लाख सोलह हजार नौ सौ रुपये मात्र) के व्यय भार का अनुमान है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को निगम द्वारा विशेष स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

- मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोले जाने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से व्यय की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है।

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अनिवार्य रोटेटिंग इण्टर्नशिप के दौरान शासनादेश संख्या-16/71-4-2021-529/1990, दिनांक 05 जनवरी, 2021 द्वारा अनुमन्य इण्टर्नशिप भत्ता 12,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की 04 मई, 2026 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया है। उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति की उक्त बैठक में 08 इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की संस्तुति की गयी है।

- मंत्रिपरिषद ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेण्ट (एफ0डी0आई0), विदेशी पूंजी निवेश (एफ0सी0आई0), फार्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इण्डिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 के अन्तर्गत इम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 19.12.2025 एवं दिनांक 07.02.2026 को सम्पन्न बैठक में 03 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किए जाने की संस्तुति/निर्णय पर अनुमोदन प्रदान किया है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 के अध्याय-छः के नियम 22 के पश्चात नया नियम-22 (क), 22 (ख) एवं 22 (ग) बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय सप्तम राज्य विधि आयोग द्वारा त्रयोदशम प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव के आधार पर लिया गया है।

- मंत्रिपरिषद ने इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के सन्निकट जनपद सुलतानपुर में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आई0एम0एल0सी0) की स्थापना हेतु अवस्थापना विकास के निर्माण कार्य ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने हेतु 27225.33 लाख रुपये की धनराशि पर अनुमोदन प्रदान किया है।

- मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु नई बसों को क्रय किए जाने के लिए 40,000 लाख रुपये की धनराशि के व्यय प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

- मंत्रिपरिषद ने साक्षर भारत योजना में 31 मार्च, 2018 तक कार्यरत रहे जिला/ब्लॉक समन्वयक एवं शिक्षा प्रेरकों के मानदेय की अवशेष देनदारियों हेतु वर्ष 2026-27 के बजट में प्राविधानित 336.91 करोड़ रुपये में से 260.53 करोड़ रुपये को अवमुक्त/स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। यह धनराशि निदेशक, साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जाएगी। अवशेष मानदेय के भुगतान की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला/ब्लॉक समन्वयक एवं शिक्षा प्रेरकों की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात ही की जाएगी।

- मंत्रिपरिषद ने स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत 25 लाख टैबलेट के क्रय हेतु निविदा से चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 237460 लाख रुपये का बजट प्राविधान किया गया है।

- मंत्रिपरिषद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (कोर्ट मैनेजर केन्द्रीयकृत सेवा) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
  उक्त नियमावली के प्रख्यापन से रिट पिटीशन (सी) संख्या-1022/1989 व उससे सम्बद्ध आई0ए0 व रिट पिटीशन (सी) संख्या-301/2024 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 मई, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा।
  साथ ही, मा0 उच्च न्यायालय एवं जनपदीय न्यायालयों के प्रबन्धन में सुगमता होगी तथा मा0 उच्च न्यायालय एवं जनपदीय न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों को दक्षतापूर्वक सम्पन्न कराने में सहायता मिल सकेगी।
  सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती होने पर मा0 उच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय कार्यों का त्वरित एवं सुगमतापूर्वक निस्तारण सम्भव हो सकेगा, जिससे जन सामान्य भी लाभान्वित होगा।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद मैनपुरी में समान पक्षी विहार के निकट पर्यटन विकास हेतु ग्राम सभा की 06 हेक्टेयर भूमि को जनहित में श्रद्धालुओं/पर्यटकों के सुविधार्थ विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार जनपद मैनपुरी की किसनी तहसील के समान पक्षी विहार के निकट ग्राम समान स्थित ग्राम समाज की ऊसर दर्ज भूमि गाटा संख्या-2447 ज़/50.72 एकड़ (22.548 हेक्टेयर) में से 06 हेक्टेयर ऊसर भूमि, जो रिक्त है, पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।